RAJYA SABHA

(Friday, the 29th April,1988|8 Vaisakha, 1910 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Short Supply of Milk at DMS and Mother Dairy Booths

*81. SHRI HARVSNDRA SINGH HANSPAL:†

SHRI RAOOF VALIULLAH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the citizens of the capital are in the grip of a severe milk shortage for the last two months;

(b) whether the booths of the Mother Dairy and Delhi Milk Scheme are not getting adequate supplies of milk;

(c) if so, what are the reasons for the milk shortage;

(d) what is the actual demand of milk in the capital per day and the total quantum of milk distributed per day and the sources of milk supplies to the capital; and

(e) the steps Government propose to take to meet the shortage?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

On the basis of a liquid milk market survey of Delhi made in 1980, it is estimated that the household demand for milk in Delhi during 1988 will be about 20 lakh litres per day.

Even though there has been a general fall in the procurement of fresh milk due to drought, the combined level of supplies of approximately 9.00 lakh litres of milk per day by Delhi Milk Scheme (DMS) and Mother Dairy during February and March, 1988 was more than what they supplied during the coresponding period of the previous years. However, as the private dairies and State Cooperative Dairy Federations, who are selling milk in Delhi, have increased their sale prices, the demand for DMS and Mother Dairy milk has increased considerably.

In order to ensure that more milk is available to household consumers, it has recently been decided that DMS will also stop supplies of milk to hotels and other commercial institutions and also reduce the quantities of milk to be supplied to home delivery agents. DMS has also stopped processing standardised milk so that more toned milk becomes available to the consumers through DMS booths. The Delhi Administration has also promulgated an order prohibiting the manufacture, sale etc. of milk products. Supply of milk to the consumers has been restricted to two litres per head on first come first served basis. In order to ensure availability of more fresh milk, procurement prices have been increased.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: चैयरमैन साहब, दिल्ली के अन्दर बिजली और पानी की तो शार्टेज थी ही अब दूध की भी बहुत ज्यादा शार्टेज है जिसके कारण दिल्ली मिल्क स्कीम और मदर डेयरी के बूथ्स के ऊपर बहुत लंबी-लंबी लाइन्स तो लगती ही हैं साथ ही कुछ को दूध मिलता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। इससे वहां पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। लोग तीन-तीन, चार-चार, छ:-छ: घंटे पहले जाकर अपनी बोतल, थैला या कोई और चीज लाइन में रख देते हैं और जब ये चीजें आगे-पीछे होती हैं तो फिर झगड़े होते हैं। मुझे खुशी है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन मेरा क्युश्चन स्पेसिफिक था कि दिल्ली के अन्दर रिक्वायरमेंट कितनी

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Harvendra Singh Hanspal.

है और आगामी डिमांड कितनी है ? इसके जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि 1980 के मार्केट सर्वे के अनुसार 1988 में 20 लाख लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट है । लेकिन 1980 के मार्केट सर्वे रिपोर्ट के बाद क्या कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है ? आज कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है ? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं । दूसरे मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि दिल्ली मिल्क स्कीम और मदर डेयरी 9 लाख लीटर मिल्क पर डे सप्लाई कर रहे हैं । लेकिन बैलेंस के लिए क्या इंतजाम है जिससे दिल्ली के अंदर दूध की शार्टेज खत्म हो सके ।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं कि जिस तरह से आबादी बढ़ती है उसके साथ-साथ दूध की मांग भी बढ़ती है लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा पूरी कोशिश रही है कि न केवल लोगों को दूध उचित भाव में मिले बल्कि उनकी जरूरत के मुताबिक भी मिलना चाहिए। महोदय, इतना भयंकर सूखा होने के बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल 1986 में मार्च के महीने में जो दूध दिया गया, वह 8 लाख 50 हजार लीटर पर डे दिया गया, वर्ष 1987 में 9 लाख 45 हजार लीटर प्रतिदिन दिया गया और वर्ष 1988 में इतने सूखे के बावजूद भी 9 लाख 55 हजार लीटर मार्च के महीने में प्रतिदिन दिया गया है । महोदय, जहां तक इस कमी को पूरा करने का ताल्लुक है, यह ठीक है कि 1980 का सर्वे 1988 तक के लिए किया गया था और 1988 तक सर्वे में 20 लाख लीटर प्रतिदिन दिल्ली में दूध चाहिए, लेकिन यह सारा दूध केवल मदर डेयरी या दिल्ली मिल्क सप्लाय स्कीम के तहत ही नहीं सप्लाय किया जाता बहुत से लोग वैसे ही लाकर लोगों को बेचते हैं । कुछ लोगों ने अपना साधन भी बनाया हुआ है, अपने पास भी कुछ पशु रखे हुए हैं, बाहर डेयरी फार्म बना रखे हैं, उनसे भी दूध आता है लेकिन हमारी कोशिश यह होगी कि दूध की अगर कमी है तो जो हमारा मिल्क पावडर है, मिल्क बटर है उसका इस्तेमाल करके भी उसका दूध तैयार करके लोगों को सप्लाई करते हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : आपने यह नहीं बताया कि एक्च्यूअल आज रिक्वायरमेंट क्या है । सर्वे के मुताबिक आज 20 लाख लीटर होनी चाहिए थी लेकिन है कितनी ? यह नहीं बताया और यह भी नहीं बताया कि जो बैलेंस डेफिसिट है 9 लाख लीटर और खपत के बीच में वह कैसे पूरा किया जाएगा ।

श्री भजन लाल : प्राइवेट डेयरी से ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : अगर प्राइवेट डेयरी से दे रहे हैं तो फिर शार्टेज क्यों है । शार्टेज को दूर करने की सरकार की जिम्मेदारी है । उसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रही है, यह मैं जानना चाहूंगा और दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक आज जो बाजार में, ओपन में दूध बिकता है वह 7 रु० से 7.50 रु० प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है, जो आप सप्लाई करते हैं वह आप 3.50 रु० प्रति लीटर के हिसाब से सप्लाई करते हैं । क्या यह कारण नहीं है कि मदर डेयरी और दिल्ली मिल्क स्कीम को ज्यादा दूध प्रोक्योर करने में दिक्कत होती है, उनको कठिनाई होती है । क्या आप कोई ऐसा भी विचार कर रहे हैं कि आप दूध खरीदने की कीमत बढ़ा दें ताकि दूध की प्रोक्योरमेंट और बढ़ जाये ।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, आप जानते हैं कि बात बहुत सही है इनकी कि दूध का भाव प्राइवेट जो डेयरी वाले लेते हैं वह महंगे भाव में लेते हैं और आगे बेचते भी कुछ महंगे भाव पर है, उन पर कंट्रोल भी नहीं है और मदर डेयरी, दिल्ली मिल्क स्कीम के तहत जो दूध लिया जाता है, महंगे भाव में लिया जाता है और जिस पर बेचते हैं वह कम है और महंगे भाव

में लेने की वजह से दिल्ली मिल्क स्कीम को साल में, जो साल अब गया है, उसमें तकरीबन 12 करोड़ रु० का घटा महंगे भाव में दूध लेकर के कम भाव में सब्सिडाइज करके लोगों को देने में होगा। इसी तरह से मदर डेयरी को पिछले साल 6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और इस साल उम्मीद है कि अगर भाव नहीं बढ़ा तो 16 करोड़ रु. का घाटा मदर डेयरी को भी हो जाएगा। अब भाव बढ़ाते हैं तो आम आदमी, गरीब आदमी को तकलीफ होती है कि साहब दूध का भाव महंगा हो गया लेकिन कई और डिपार्टमेंट ने और मदर डेयरी तथा दिल्ली मिल्क स्कीम ने बार-बार अनुरोध किया है सरकार से कि इसका भाव बढ़ाना चाहिये तो इस पर हम विचार कर रहे हैं लेकिन अभी तक बढ़ाया नहीं गया और न अभी तक बढ़ाने की कोई ऐसी योजना है, लेकिन इस पर विचार कर रहे हैं कि बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाये। यह मामला केबिनेट में आएगा और उसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Valiullah.

SHRI RAOOF VALIULLAH: Sir, part (b) of the question is what steps the Government proposes to take to meet this shortage. Sir, it is strange that in the answer the Minister has mentioned all kinds of restrictions and curbs put on the supply and also on consumption. But he has not mentioned how the procurement of fresh milk will be strengthened and how the supply to the Capital City of Delhi of fresh milk is going to be augmented. Therefore, I would like to know from the honourable Minister whether any steps have been taken to procure milk from the adjoining States. Sir, it is unfortunate that there is an acute shortage of water in Delhi. Otherwise, the private traders will add water to the milk. But there is shortage of even water in the Capital. Therefore, I would like to know whether the honourable Minister will, first of all, see that the prices which the private traders have raised are reduced and they do not get away with unilaterally raising their prices thereby playing with the lives of the people of the Capital.

Sir, in some areas in Delhi, for days together milk supply has not been there and milk is not available. Therefore, I would like to know what positive steps have been taken by the Government, apart from putting curbs on the supply and restrictions on consumption.

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, मैंने अभी आंकड़ों से बताया कि दूध की मात्रा घटी नहीं है। दूध का वितरण करने का सिस्टम है। दूध की मात्रा जो वितरण में है उस मात्रा को देखना चाहिये। उससे लगता है कि दूध की मात्रा फालतू है, कम होने का सवाल ही नहीं है। आप जानते हैं कि आबादी बढ़ती है तो दूध की मांग भी बढ़ती है और उस मांग को पूरा करने के लिए हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दूध लिया जाए। आप जानते हैं कि स्टैण्डर्ड आफ लीविंग भी बढ़ गया है। बच्चों को दूध चाहिये। हर साल दो परसेंट आबादी बढ जाती है उसका भी ध्यान रख कर हमारी कोशिश यह है कि ज्यादा दूध लोगों को मिले। पाउडर का बढ़िया दूध बनाकर मक्खन से दूध बनाकर लोगों को देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम मक्खन से भी दूध बनाते हैं और पाउडर से भी सपरेटा दूध बनाते हैं। जनवरी, 86 में 2.44 टन प्रतिदिन मिल्क पाउडर से दूध बना। 86–87 में 6.87, 87–88 में 9.65 टन मिल्क पाउडर से दूध बना। अब अप्रैल का महीना चल रहा है। 1986 में 12.77 टन पाउडर से दूध बनाते थे और 1.53 मक्खन से। इसी तरह 87 में 19.32 टन पाउडर से और मक्खन से 2.58 टन से दूध बनाते थे। और 88 में . . .

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, the answer is not relevant.

PROF. C. LAKSHMANNA: How will you make milk from butter?

श्री भजन लाल : आप तसल्ली रखिए एक मिनट सुन लीजिये । मैं जो कह रहा हूं वह सही है ।

श्री रऊफ वलीउल्लाह : जिस तरह से पानी हरियाणा से ले रहे हैं क्या दूध भी लेंगे ?

श्री भजन लाल : सुनने की कृपा करें हम यह चाहते हैं कि पड़ोसी प्रदेशों से दूध लें । चाहे यू०पी० हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यहां तक कि गुजरात को भी नहीं छोड़ेंगे । स्टेटों में फेडरेशन बनी हुई हैं उनके द्वारा दूध यहां मदर डेयरी में आता है । यह ठीक है कि जो आपने कहा कि दूध से मक्खन बनता है लेकिन जब दूध की कमी होती है तो बटर और पाउडर को मिलाकर और पानी मिलाकर दूध की शक्ल में बेचा जाता है ताकि उसके कन्टेंट्स पूरे किये जा सकें । उसमें जितनी मिकदार होनी चाहिये उसी रेशो से हम मिलाते हैं । हम यही चाहते हैं कि लोगों को पूरे फैट्स और अच्छा दूध मिल सके ।

श्री हरि सिंह : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह तो सच है कि दिल्ली में दूध की कमी है । इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने अपनी कोशिशें जाहिर की हैं लेकिन मेरी जानकारी यह है कि वीकर सेक्शन और बैकवर्ड क्लास के लोगों ने दिल्ली में दूध की सप्लाई करने के लिये अपनी सोसाइटीज की रजिस्टर्ड कराने के पश्चात् अप्लाई कर रखा है लेकिन सोसाइटी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा है ताकि वे दूध सप्लाई कर सकें । ऐसा क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, ऐसा मेरे नोटिस में नहीं आया है । यह आज ही सुना है । इस बात को जरूर दिखवाऊंगा । अगर कोई सोसाइटी है और दूध देना चाहती है और उनकी सोसाइटी का नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो मैं जरूर दिखवाऊंगा । यदि कोई भी नाइंसाफी की बात है तो ठीक किया जायेगा ।

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Chairman, Sir, while replying to the supplementaries, the Minister went on talking about the increasing population. There is nothing new about it. If there had been a survey and projection of 20 lakh tonnes of milk which is required for the year, they would have been taken the increasing population also into consideration. Therefore, they were aware of the gap between the supply and demand for the last three years, as stated by the Minister himself. I would like to know from him what specific steps were taken in the preceding two years to meet the possible shortage of milk in the current year.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, मैंने अभी डिटेल में बताया कि दूध की मांग बढ़ी है, यह ठीक बात है । दिल्ली में सर्वे के मुताबिक 19—20 लाख लीटर दूध प्रतिदिन चाहिये । लेकिन जो दोनों हमारे दारे हैं डी० एम० एस० और मदर डेरी इनके द्वारा तकरीबन साढ़े नौ लाख लीटर दूध प्रतिदिन हम देते हैं । जो हमने डिपो खोल रखे हैं उन पर जितने लोग आते हैं, तकरीबन सब को दूध दिया जाता है, . . . (व्यवधान) ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : यह बात सही नहीं है. . . (व्यवधान) ।

श्री भजन लाल : इस सम्बन्ध में भारत सरकार जो कर सकती है, जो सहायता कर सकती है वह कर रही है । भारत सरकार कानूनी तौर पर जो प्रतिबन्ध लगा सकती है वह प्रतिबन्ध उसने लगाया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूध मिल सके । खोया बनाने पर, छेना बनाने पर इन गर्मियों के दिनों में बैन लगा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध उपलब्ध हो सके । इसके लिये हमने भरसक कोशिश की है । जैसा मैंने पहले भी अर्ज की है कि हमारी पूरी कोशिश है कि पशुओं की नस्ल सुधारी जाय ताकि अच्छा और ज्यादा से ज्यादा दूध देश में पैदा हो । इसके लिए हम आपरेशन फ्लड–3 में पैसा भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं ताकि लोगों को अच्छा और

ज्यादा से ज्यादा दूध उपलब्ध हो सके। आप जानते हैं कि पिछले दो तीन सालों में भयंकर सूखा पड़ा है और राजस्थान और गुजरात से जो बहुत बड़ी मात्रा में दूध आता था उसमें दिक्कत आई है। लेकिन फिर भी हमारा जो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है उसमें हमने पिछले दिनों में फालतू दूध इस साल वितरित किया है।

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, the Minister is giving contradictory logic, about the reason why there is shortage. You say that during the last three years 9.6 per cent or some proportion of milk is available in Delhi. But at the same time you say that the population growth is 2.8 per cent. So the population is increasing, while the milk is in short supply. But I shall not go into his contradictions. Now my friend has brought it to your notice, and you yourself are aware, the consumers are harassed particularly; I have myself seen long queues.

There are two ways of solving this problem. As you have rightly accepted yourself, the private vendors are selling milk at Rs. 7 or Rs. 8 per kg. In Bombay it is Rs. 12 per kg. The difficulty, which seems to me, is that proper price is not given for cow's milk. The prices of inputs like grass, etc. have increased. So on this basis you have to re-consider to pay more price to producers so that more milk is available.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI A. G. KULKARNI: Yes. Will he consider paying more price to them? Secondly, you have yourself agreed that milk powder imported from European countries is mixed and toned milk is given. I want to know, what is the exact proportion of fat in the toned milk and the price concerned with it? Have you also taken cognizance of the widespread criticism that the milk powder is affected by Chernobyl or it has nuclear effect? There is a wide criticism in the world and in the Third World countries also. I want to know how much Chernobyl contaminated powder you have used for supply of toned milk? And will you pay a better price to the producers?

श्री भजन लाल: सभापति महोदय कुलकर्णी जी बहुत पुराने, सीनियर और सूझबूझ वाले मैम्बर हैं।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी: सीनियरिटी क्या करेगी यहां?

श्री भजन लाल: बहुत सूझबूझ वाले कहा है, अच्छी बात कही है... (व्यवधान)... आप सुनने की बात करिये कृपा करके।... (व्यवधान)... मैंने कहा सूझबूझ वाले। यह अच्छी बात है बुरी तो कोई बात नहीं कही मैंने। आपका तजुर्बा लम्बा है।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी: मुझे सीनियर बोलकर जवाब नहीं देते है यह मेरी प्राबलम है।

श्री भजन लाल: आपने दो सवाल पूछे हैं। दो बातें आपने पूछीं। एक तो यह पूछी कि जो टोन्ड मिल्क बनता है उसमें कितना प्रतिशत फैट होता है। 3 प्रतिशत फैट उसमें होता है। आप जानते हैं कि गाय के दूध में तकरीबन 3-4 प्रतिशत फैट होता है। इसलिये 3 प्रतिशत फैट करके इसको बेचा जाता है ताकि फैट के हिसाब से यह ठीक रहे।

दूसरी बात आपने पूछी...

SHRI A. G. KULKARNI: Nuclear-montaminated milk-powder....

श्री भजन लाल: मैं अभी आप से कह रहा था कि प्रोटीन 8.5 प्रतिशत होना चाहिये और फैट 3 प्रतिशत होना चाहिए।

श्री सभापति: पाउडर के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री भजन लाल: मैं ... के बारे बता रहा हूं कि...

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, he is avoiding to give the reply about nuclear-contaminated milk-powder imported by the NDDB and supplied to

the consumers all over the country affecting the young children, etc. Would you please have mercy on the consumers?

श्री सभापति : क्वेश्चन है कि चिरनोबिल से अफेक्टेड जो दूध पाउडर है इसको ऐक्जामिन कर रहे हैं या नहीं ?

श्री भजन लाल : मेरे पास आंकड़े हैं। मैंने टोनु मिल्क के बारे में कहा है कि 3 प्रतिशत उसमें फैट है और 8.5 प्रतिशत प्रोटीन है।... (**व्यवधान**) आप सुनेंगे मेरी बात को, मैं आपको बताता हूं... (**व्यवधान**)...

सभापति महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार कोई भी बाहर से पाउडर या बटर ऐसा नहीं लायेगी जो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : लाये हैं।

श्री भजन लाल : बिल्कुल नहीं। लाने का सवाल ही नहीं है, देने का सवाल ही नहीं है। इसके लिये बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है और उसमें लिखकर दिया है कि हम बाकायदा अपने स्टैण्डर्ड के मुताबिक लेंगे। हिन्दुस्तान की धरती पर वही पाउडर या बटर आयेगा जो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। देश के लोगों, देश के किसी भी व्यक्ति की जान, उनकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जायेगा। जो आएगा वह बिल्कुल स्टैण्डर्ड के मुताबिक आयेगा। मैं आपको और सारे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं यह बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक आयेगा। मैं आपको दूध के पिछले साल के भाव के बारे में जरा बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : भाव नहीं पूछा है।

श्री भजन लाल : उन्होंने भाव पूछा है। 1986-87 में किसानों से 3.85 पैसे के भाव से हमने लिया नवम्बर से फरवरी तक। 1987-88 में इसी अवधि में 4.85 रुपये के भाव से यानी 1 रुपया प्रति किलो किसानों को ज्यादा देकर लिया जब कि हमने इन तीन सालों में दूध लेने वालों के लिये कोई बहुत कीमत नहीं बढ़ाई जबकि हमने एक रुपया ज्यादा देकर किसानों से खरीदा।

SHRI A. G. KULKARNI: What is the price of grass? What is the price of feed? Do you know the price of the feed? And you say that you are the Agriculture Minister.

श्री भजन लाल : कंज्यूमर्स को हमने उसी भाव में दिया है। इस तरह से... (**व्यवधान**)...सुन लीजिए कृपा करके। ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बैठ जाइये आप।

श्री भजन लाल : आप जरा सुनने की कृपा करें। ..(**व्यवधान**) ....

आप जैसे आदमी की प्रान्तों को जरूरत है ज्यादातर हरियाणा में।

मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 1987 में अप्रैल और जुलाई में 4.45 रुपये दिया था और इस दफा 5.75 रुपये जिनसे दूध लेते हैं उनको दिया है। पांच रुपये पच्चहत्तर पैसे प्रति किलो ले कर तीन रुपये तीस पैसे तीन पचास पैसे प्रति किलो की दर से दिल्ली के उपभोक्ताओं को दिया है।

SHRI SUNIL BASU RAY: Sir, my question is that the supply of milk depends on the availability of milk in the villages, and that, in turn, depends upon whether there are sufficient number of cows and buffaloes, which are healthy and have a yield of milk which is above average. So, may I know whether we have got sufficient number of cows and buffaloes which are healthy and yield better and greater quantity of milk? Has the Minister got any assessment made on this aspect of

the question? Unless we develop these cow-herds and buffaloes, we will not be able to supply sufficient quantity of milk to the town people. Can the Minister reply on this point or not?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब तक पशुओं की नस्ल सुधारने का काम तेजी से नहीं चलेगा तब तक दूध का उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए हम करोड़ों रुपये खर्च करने जा रहे हैं। आप्रेशन फ्लड-तीन में ज्यादा दूध पैदा करने के लिए सरकार 915 करोड़ रुपये खर्च करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध उपलब्ध कराया जा सके और पशुओं की नस्ल के सुधार में खास तौर से वृद्धि की जा सके। इसके लिए प्रोग्राम बनाए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 1950-51 में। (व्यवधान)

श्री सभापति : इतिहास मत बताइये आप अपना जवाब संक्षेप में दीजिये।

श्री भजन लाल : दूध का उत्पादन 460 लाख टन हो गया है लेकिन तीन साल तक सूखा पड़ने के बावजूद (व्यवधान)

श्री सभापति : यह बात आप दस बार कह चुके है। अब बैठ जाइये।

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has stated that the supply of milk is less than the demand. For that purpose you have to streamline your distribution system. The Minister has stated that for hotels they have to stop the supply. But has the Minister taken care to see that from the booths the milk instead of being given to the consumers is not passed on to the hoteliers as they keep ten to fifteen people in the queue and draw as much milk as they want.

MR. CHAIRMAN: Mr. Desai, you put your question.

SHRI JAGESH DESAI: Sir, I would like to know what action the Government is going to take to see that the milk intended for the consumers is not passed on to the hoteliers and bulk consumers. I would also like to know whether the Government is thinking of issuing milk cards so that on the production of those cards only milk will be supplied, in order to ensure that only the real consumers get the milk. What scheme has the Government in this regard?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, कोशिश तो हमारी यही होती है कि सही उपभोक्ता को दूध मिले जरूरत वाले को मिले। कहीं से कोई शिकायत इनके पास आई हो कि गलत आदमी दूध ले गया तो हमें लिख कर के माननीय सदस्य भेज दें हम कार्यवाही करायेंगे लेकिन यह जो जनरल बात है यह नहीं (व्यवधान)

SHRI JAGESH DESAI: They have to streamline the distribution system.

MR. CHAIRMAN: He is trying to do it. (*Interruptions*).

SHRI JAGESH DESAI: But they must have some system.

MR. CHAIRMAN: Next question, Q. No. 82.

Consumer Protection Councils in the States

*82. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the names of the States which have not so far set up State level Consumer Protection Councils;

(b) whether the Central Government have issued any directions/guidelines to the States in this regard and if so, the details thereof; and

(c) whether the Central Government have any machinery to look into the functioning of these Councils?